भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 682
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।
.....
राज्य और जिला यमुना समितियों की स्थापना

682. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला गंगा समितियों की तर्ज पर राज्य और जिला यमुना समितियों का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए गंगा नदी की सफाई के प्रयासों में इसी प्रकार की जिला गंगा समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद ऐसी समितियों का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यमुना नदी के संरक्षण के लिए निगमित क्षेत्र के वित्तीय और तकनीकी दोनों अंशदानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): दिनांक 7 अक्टूबर 2016 की प्राधिकरण अधिसूचना के अनुसार, राज्य गंगा पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन समिति और जिला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन हर निर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करने के लिए किया जाना अपेक्षित होता है।

(घ): स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) दिनांक 21.01.2015 को स्थापित की गई ताकि इसमें प्रवासीय भारतीय, देशी और विदेशी कॉर्पोरेट, अप्रवासीय भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) गंगा नदी के संरक्षण प्रयासों में योगदान कर सकें।